DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c)

ALL INDIA RADIO:

Depending upon the availability of technical facilities and talent available, the Stations have been allowed to originate commentaries in regional languages.

DOORDARSHAN

Doordarshan has a single channel for all its telecasts. Since Doordarshan has to broadcast commentary both in English and Hindi, it is not possible for it to undertake commentaries in the regional languages.

Labour Court at Chandigarh

3445. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no Labour Court is functioning at Chandigarh for the last six months;

(b) if so, how many cases of labour references by Government have remained unattended; and

(c) the steps proposed to expendite the setting up of labour court at Chandigarh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) No, Sir. Central Government Industrial Tribunalcum-Labour Court set up recently at Chandigarh is functioning.

(b) Question does not arise.

(c) Not applicable.

राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों में विद्युतीकृत नलकूप

3446. **श्री विरदाराम फुलवारिया**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों में अक्तूबर, 1983 तक कितने नलकूपों को बिजली दी गई है और कितने नलकूपों को दी जानी शेष है; और

(ख) उन्हें कब तक बिजली दे दी जाएगी और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) राजस्थान में ट्यूबवैलों के ऊर्जन के संबंध में जिलेवार ब्यौरा केवल 30.9.83 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। उक्त तारीख को राजस्थान के जालौर जिले में 9136 ट्यूबवैल तथा सिरोही जिले में 5489 ट्यूबवैल ऊर्जित थे। 1983-84 के दौरान 9730 पम्पसैटों को ऊर्जित करने के लक्ष्य में 9000 पम्पसैटों को ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत ऊर्जित किया जाना है और 730 पम्पसैटों को राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जित किया जाना है। वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत जेलौर जिले में 305 पम्पसैटों और सिरोही जिले में 105 पम्पसैटों को ऊर्जित करने का कार्यक्रम बनाया है। राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जित किए जाने वाले 730 पम्पसेटों का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 1983-84 (30.9.83 तक) के दौरान जेलौर जिले में 78 पम्पसेटों तथा सिरोही जिले में 41 पम्पसैट ऊर्जित किए गए थे। अगले वर्षों के लिए कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Shortage of cooking coal

3447. SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of cooking coal from indigenous sources; if so, what is the short fall against actual target and requirement;

(b) whether large quantities of cooking coal are being imported to make up the shortage, particularly for the steel industry; if so, at what cost; and

(c) what remedial action Government envisage in this direction and when we are likely to become self-reliant in this item?

THE MINISTER OF STATE IN THE

DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI BALBIR SINGH) : (a) to (c) Supply of cooking coal from indigenous sources to steel plants during the period April-November, 1983 was 94.29 lakh tonnes as against the consumption of 93.22 lakh tonnes during this period. The stock of indigenous cooking coal with the steel plants has increased to 3.90 lakh tonnes as on 2.12.1983 as against 1.66 lakh tonnes as on 1.8.1983. However, since there is a gap between the overall assessed demand of cooking coal and indigenous availability, small quantities of cooking coal are being imported. During the current year 0.198 million tonnes of cooking coal has been imported (shipped) upto 27.11.1983 costing Rs. 15.90 crores. Efforts are being made to augment the supply of indigenous cooking coal by the sitting up of new washeries and mine projects.

बाड़मेर जिले में कपूटड़ी में लिग्नाइट संयंत्र

3441. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में कपूटड़ी गांव में, जहां लिग्नाइट का बड़ी मात्रा में भंडार है, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण का कार्य नेवेली लिग्नाइट निगम को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसके निर्माण के लिए धनराशि कैसे जुटाई जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) बाड़मेर जिले के कपूरडीह क्षेत्र में लिग्नाइट भंडारों का विस्तृत रूप से पता लगाने और इस क्षेत्र में खनन योग्य लिग्नाइट के भंडारों का निर्धारण करने का कार्य सरकार ने मैसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि० को सौंपा है। कपूरडीह में विद्युत केंद्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर केवल तब विचार किया जा सकता है जबकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वर्तमान खनन योग्य लिग्नाइट भण्डार विद्युत केन्द्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। उपर्युक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी के चयन और इसके लिए निधियां उपलब्ध कराने का प्रश्न तब उठेगा जब कि स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाती है।

नाथपा झाकड़ी परियोजना

3449. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकड़ी बिजली परियोजना में राजस्थान राज्य का कितना हिस्सा है;

(ख) उक्त परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्थान को उसके हिस्से की बिजली देने में बाधा डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान सरकार को क्या सहयोग देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ख) हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश संबंधी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। विद्युत के आबंटन के बारे में निर्णय निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

राज्यों में विद्युत उत्पादन

3450. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड बिजली की आवश्यकता और मांग को पूरा करने में बिलकुल असमर्थ हैं तथा इस स्थिति के आगामी दो-तीन वर्षों में भी कमी चलते रहने की संभावना है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत